

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक/एफ-5/898/2019/10-11/902
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/3/20

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल,
जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- जबलपुर जिले में उच्च स्तरीय पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.090 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, (जल उत्पादन) नगरपालिक निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर का पत्र क्र0/मा0चि0/9622 दि0 16.10.2019

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) for the 0.090 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- No felling of trees shall be done.
- 5- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- 6- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.

-2-

- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No labour camp shall be established on the forest land.
- 10- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 15- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 16- No work shall be done during night.
- 17- प्रकरण में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सभी प्रावधानों, प्रमुखता 38 (0)(1) (जी) का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजा जावेगा।
- 18- वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर इस कार्य से वनक्षेत्र एवं वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए मौके स्थल का भ्रमण कर सभी आवश्यक उपायों के साथ में की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में निर्देश आवेदक संस्थान को जारी करेंगे। आवेदक संस्थान इन निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

19- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

82
04/03/2020
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/898/2019/10-11/903

भोपाल, दिनांक 4-3-20

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 - 2- कार्यपालन यंत्री, (जल उत्पादन) नगरपालिक निगम, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sonaw
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल